



भारत कि कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

अभूतपूर्व ढंग से बढ़ाया गया पेट्रोल की कीमतों का विरोध करते हुए

31,मई 2012 को अयोजित की जा रही 'भारत बंद' को सफल बनावे!

प्रेस विज्ञप्ति

दि: 25/5/2012

प्रिय भारत की जनता!

हमारे देश की शासक वर्गों ने साम्राज्यवादियों की विशेषकर अमेरिका साम्राज्यवादियों की एल.पी.जी आर्थिक नीतियों को जब से अपनाया शुरू की तब से महंगाई बढ़ना और तेज हुई है। यु.पी.ए – 2 की शासन काल में महंगाई बढ़ने में कोई सीमा ही नहीं होने के चलते देश के आम आदमी का जीवन काफी दुर्बल बनी है। यु.पी.ए – 2 सत्ता में आने की तीसरी वर्षगांठ की समारोह को बड़ी जोरशोर से अयोजित कर देश के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने बेशरम से यूँ कहा की देश में गरीबी बढ़ी तेजी से घट रही है। ऐसे उन्होंने कोरा झूठ कहने के दुसरे दिन ही देश के जनता को उन्होंने अपूर्वस्तर पर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाते हुए काफी कड़वा तोफा दि है। विडंबना यह है की देश की प्रधानमंत्री एवं पेट्रोल मंत्री जनता के सामने ऐसा एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिए है की पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के पीछे उनकी कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार के इस रवैया को और बढ़ाया गया पेट्रोल की कीमतों को खंडन करते हुए उसके विरोध में की जा रही मई 31 **भारत बंद** को सफल बनाने हेतु हमारी पार्टी भारत की जनता से अनुरोध करती है।

पेट्रोल कंपनियों का कहना यह है की पेट्रोल की दर बढ़ाने के पीछे डॉलर के साथ रुपया का अवमूल्यन ही एक मात्र वजह है। लेकिन वास्तव में हमें यह समझना है की देश की शासक वर्गों से अपनाई गई दिवालियपन मुद्रा नीति ही उसके लिए असली जड़ है। देश में मुद्रास्फिती सरकार के आंकड़ों के मुताबिक विगत कुछ समय से दो आंकड़ों की नजदीक धूम रही है। देश में लगभग 15 लाख करोड रूपयों का विदेशि मुद्रा भंडार होने को गर्व के साथ बताते आई सरकार ने फिलहाल उसमें तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए जनता के सामने अपनी मूँह मोड़ रही है। दिन – ब – दिन बढ़ते जा रहे आर्थिक संकट से देश को बाहर लाने के नाम पर रेपो रेट को घटाना, सी.आर.आर. को घटाना जैसे कई प्रकार के एक्सरसाईज करने के बावजूद भी मुद्रास्फिती को काबूम रखने में असमर्थ रही केंद्र सरकार व्यापारियों के सामने घुटने टेककर आम आदमी का सहन की बड़ी परिक्षा ले रही है। विगत 14 महिनों में 10 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ना देश की जनता के सामने एक बड़ा चुनौती भरा सवाल बन गई। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का मतलब यह है कि वह सभी क्षेत्रों को उसकी चपेट में लेते हुए बाजार में अन्य सभी चीजों की महंगाई को बढ़ा कर जल रही सधारण आदमी का जीवन को चिलचिला ते धूप में फेंकने के जैसे करेगी।

भारत की शासक वर्गों द्वारा अमल कि जा रही एल.पी.जी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारत के अर्थव्यवस्था वास्तव में गंभीर संकट में फसी हैं। लेकिन देश के यु.पी.ए सरकार ने खुशि से यह कहती है की भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर दुनिया में दुसरी नंबर पर है। दुसरी ओर वह सरकार देश में दिन प्रति दिन आम जनता झेल रही गरीबी, बेरोजगारी, ऋण की बोझ, महंगाई, अशिक्षा एवं अस्वास्थ्यता जैसे गंभीर समस्याओं को हल करने में बुरी तरह विफल रही है। इस के बावजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग से लेकर योजना आयोग की अध्यक्ष मोन्टेक सिंग अहलुवालिया तक कई सरकारी अर्थशास्त्रियों ने गरीबी घटने की आंकड़े पेश कर रहे है। इन लोगों ने देश की आर्थिक क्षेत्र में सामने आ रही सभी समस्याओं का मूल कारण सब्सिडियों को बता रहे है। इन लोगों ने पेट्रोल और युरिया को (खाद) सब्सिडी से हटा कर बाकि चीजों को भी हटाने की दिशा में आगे बढ रहे है। यह गरीबों का जिंदगी को और दुर्बल करेगी। गरीबों की जेब को काट कर बड़े कार्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली साम्राज्यवादि आर्थिक नीतियों जब तक इस देश में अमल होगी तब तक सत्ता में भले ही यु.पी.ए सरकार हो अथवा एन.डी.ए सरकार हो या संशोधनवादियों द्वारा सामने लाया जा रही तीसरी फ्रॉन्ट हो जनता की जीवन में कोई मौलिक तबदीली नहीं होगी। विगत 65 वर्षों में इस देश की शोषणवादि राजनीति इस बात को बार – बार साबित की है। इस देश में स्वावलंबना आर्थिक नीतियां, जनवादि राजनीतिक नीतियों को अपना ते हुए कृषि एवं उद्योग को समन्वय रूप से विकास करने की मकसद को लेकर उत्पीडित जनता की हित में सरकारें गठन होन पर ही महंगाई पर रोक, मुद्रास्फिती पर रोक पाना संभव

होगा। यह सत्य विगत में समाजवादि रूस एवं चीन में साबित हुई है। उस दिशा में वर्तमान में संघर्ष कर रही झारखंड, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र (गडचिरोली, चंद्रपूर,गोंदिया,भंडारा) उडिशा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगा, बिहार की जनता देश की जनता के साथ भारत बंद में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु हमारी पार्टी अपील कर रही है।

देश में ग्रीन हंट के नाम से भारत के शासक वर्गों द्वारा चलाई जा रही गृह युद्ध जैसे परिस्थितियों के बीच में कई तकलीफे झेल रही जनता को विशेषकर आदिवासी जनता को आज कि मूल्य वृद्धि कितना दुर्बर होगा नही बता सकते। एक तरफ हाट बाजारें बंद होकर, सामान सही रूप से न पा रहे संघर्षशील जनता को दूसरी तरफ पेट्रोल की किमतें बडना उनके दिक्कतों को दुगुनी करेगी। अथः इस लूटेरे सरकारों को हराकर वैकल्पिक व्यवस्था को कायम करने की दिशा में आगे बड रही जनता इस मूल्य वृद्धि के विरोध में चल रही संघर्ष में भी अग्रिम पंक्ति में खडा होने के लिए हमारी पार्टी अनुरोध कर रही है।



(अभय)

प्रवक्ता,

केन्द्रीय कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी),